समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 18 August 2026

1956 मे खंनन मंत्रालय बेचने का आरोप, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर किया हमला

Publisher

Published on 06 Oct 2025

भारतीय राजनीति में एक बार फिर पुरानी घटनाओं को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए 1956 में खनन मंत्रालय बेचने का आरोप लगाया है। दुबे ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया और मीडिया इंटरव्यू के माध्यम से उठाया और कांग्रेस को निशाने पर लिया।

सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में खनन मंत्रालय की संपत्ति और संसाधनों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। उन्होंने 1956 की घटना का हवाला देते हुए बताया कि तत्कालीन खनन मंत्री केडी मालवीय के कार्यकाल में मंत्रालय को बेचा गया था। दुबे ने यह भी उल्लेख किया कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज ने मामले की जांच की थी और यह जांच सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज है।

निशिकांत दुबे का यह आरोप न केवल कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए है, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी है कि पुराने मामलों की जांच और जिम्मेदारियों को सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई नीतियों और निर्णयों ने देश के खनन क्षेत्र को प्रभावित किया और संसाधनों के साथ असंगत तरीके से व्यवहार हुआ।

दुबे ने कहा कि खनन मंत्रालय की संपत्ति और संसाधनों का बेच दिया जाना एक गंभीर मामला है। इसके चलते न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि खनन उद्योग और पर्यावरण पर भी असर पड़ा। उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह की घटनाओं ने सरकारी संस्थाओं और जनविश्वास को कमजोर किया।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार निशिकांत दुबे का यह बयान आगामी चुनावों और राजनीतिक बहस के लिए भी अहम साबित हो सकता है। यह मामला कांग्रेस और बीजेपी के बीच पुराने मुद्दों और जिम्मेदारियों को लेकर चल रही सियासी लड़ाई का नया अध्याय जोड़ता है।

बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि 1956 में खनन मंत्रालय की बिक्री और उससे जुड़े विवाद को आज भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे भविष्य में नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। दुबे ने जनता और मीडिया से

अपील की कि पुराने मामलों पर नजर रखी जाए और ऐसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो।

कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप पर अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान आगामी समय में चुनावी रणनीतियों और विपक्षी आलोचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निशिकांत दुबे ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए कांग्रेस की पुरानी नीतियों और कार्यों को उजागर किया।

इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी सांसद के आरोपों ने न केवल कांग्रेस की पुरानी नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि यह दिखाया कि इतिहास और पुराने प्रशासनिक निर्णय आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं। निशिकांत दुबे के अनुसार, खनन मंत्रालय की संपत्ति और संसाधनों को बेचने की यह घटना न्यायिक निगरानी और जांच के बावजूद विवादित रही।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान से कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट जज की जांच का भी हवाला दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामले की गंभीरता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रही।

इस प्रकार, निशिकांत दुबे का यह बयान 1956 की पुरानी घटना को सार्वजनिक चर्चा में लाने का प्रयास है। खनन मंत्रालय के बेचने के आरोप और सुप्रीम कोर्ट जांच का हवाला यह दर्शाता है कि राजनीतिक मुद्दों में इतिहास और न्यायिक रिकॉर्ड का महत्व अभी भी बरकरार है।

आने वाले समय में यह देखना रोचक होगा कि कांग्रेस इस आरोप का क्या जवाब देती है और बीजेपी इसे किस तरह से राजनीतिक बहस और चुनावी रणनीति में शामिल करती है। निशिकांत दुबे का यह बयान भारतीय राजनीति में पुराने विवादों और प्रशासनिक निर्णयों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का अवसर बना है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.